भारत मालदीव विकास सहयोग: अवसर और चुनौतियां

*डॉ. एम. समता**

प्रस्तावना

जातीय, भाषाई, संस्कृति, धार्मिक और व्यापारिक संपर्क भारत और मालदीव के द्विपक्षीय संबंधों को लम्बे समय से जोड़ते रहे हैं। भारत वर्ष 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के पश्चात इसे मान्यता प्रदान करने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था। इसने वर्ष 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया। तभी से ये द्विपक्षीय संबंध 'सभी स्तरों पर नियमित संपर्कों द्वारा पोषित और मजबूत' होते रहे हैं। मालदीव की कार्यनीतिक अवस्थिति और भू-राजनीतिक कारक दोनों देशों की संप्रभुता तथा परस्पर सहयोग और सम्मान की संचालक शक्तियां रही हैं।

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सहयोग दक्षिण-दक्षिण सहयोग की रूपरेखा और औपनिवेशिक चरण के पश्चात विकासशील राष्ट्रों के बीच एकता और भागीदारी पर आधारित सिद्धांतों द्वारा संचालित/निर्देशित होता रहा है। भारत की विकास सहायता से, जो हालांकि मात्रा में कम है, 'इसके पड़ोसियों को (इसकी) उदार शक्ति का लाभ उठाने में' सहायता मिली है।

पश्चिमी विकास सहायता के विपरीत, भारत का विकास सहयोग बगैर किसी शर्त के प्रदान किया जाता है। इसका समन्वय विदेश मंत्रालय (एमईए) और विकास सहायता प्रशासन (डीपीए) के माध्यम से किया जाता है। भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम (प्रशिक्षण) और एक्जिम बैंक (ऋण श्रृंखला) संरचनाएं भी अल्पविकसित देशों (एलडीसी) में विकास परियोजनाएं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं।

मालदीव में विकास परिदृश्य

हिन्द महासागर में मालदीव की भू-कार्यनीतिक अवस्थिति एशिया के इस सबसे छोटे अल्पविकसित देश में इस क्षेत्र से बाहर की शक्तियों की गहरी रूचि का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। 'मालदीव की जनसंख्या 30 लाख है और भू क्षेत्र 300 वर्ग किलामीटर से कम है।' तथापि, जलवायु परिवर्तन, आंतरिक प्रवास, संसाधन-घाटा प्रभावित अर्थव्यवस्था और बिखरी हुई जनसंख्या जैसी कुछ विकासात्मक चुनौतियां हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक रही हैं। उदाहरण के लिए, मानव विकास रिपोर्ट (एचडीआर) 2014 के अनुसार, मालदीव की वार्षिक औसत विकास दर 2000-2005 के दौरान 1.7 प्रतिशत थी, जबकि वर्ष 2010-15 के दौरान मामूली वृद्धि के साथ इसके 1.9 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है।

भले ही सम्पूर्ण आय स्तर बढ़ते रहे हैं, पर माले और प्रवाल द्वीपों के बीच आय असमानताएं इसके अनुरूप कम नहीं हो रही हैं। मालदीव की मानव विकास अनुसूची (एचडीआई) के बिलकुल हाल के आंकड़ों में बताया गया है कि इसकी राजधानी माले की सम्पूर्ण मानव विकास अनुसूची (एचडीआई) मूल्य (0.734) राजधानी को छोड़कर सभी प्रवाल द्वीपों के संचई मानव विकास अनुसूची (एचडीआई) मूल्य (0.627) से अधिक है।

मालदीव में शहरीकरण का वर्तमान परिदृश्य एकसमान विकास के अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए, 'एक तिहाई जनसंख्या माले के शहरी क्षेत्रों में रहती है और इसमें से 58 प्रतिशत प्रवासी हैं जो अनेक सामाजिक समस्याएं पैदा करते हैं।' आंतरिक प्रवास 'स्कूलों, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं और माले से बाहर रोजगार के अवसरों जैसे भौतिक तथा सामाजिक आधारभूत ढ़ांचों की उपलब्धता में भेदभाव' के कारण हो रहा है। उदाहरण के लिए, मालदीव में 37.5 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन-सहन के स्तर जैसे कारकों पर आधारित बहुआयामी गरीबी का सामना कर रही है। इस प्रकार, सीमित आवास क्षमताओं और रोजगार के सीमित अवसरों के साथ-साथ माले में पहले से ही दबाव झेल रहे आधारभूत ढ़ांचे पर आंतरिक प्रवास से दबाव बढ़ रहा है।

अत: उपजाऊ तथा कृषि योग्य जमीन की कमी जैसी भौगोलिक बाधाओं के साथ-साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन भी एक ऐसी चुनौती है जो आर्थिक विविधता में बाधक है और जिससे भविष्य में निपटना होगा। विश्वबैंक का अनुमान है कि मालदीव का वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास वर्ष 2014 में 4.5 प्रतिशत रहेगा जो वर्ष 2014 में दक्षिण एशिया के 5.3 प्रतिशत अनुमानित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद विकास से भी कम है।

अन्य विकासात्मक चुनौतियों में बढ़ते समुद्र स्तर, प्राकृतिक आपदाएं और सतत स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, तटवर्ती अवसंरचना और बिखरे छोटे समुदायों के लिए रोजगार की उपलब्धता शामिल हैं। मालदीव में वर्ष 2005-12 के दौरान लगभग 4,500 व्यक्ति (प्रति दस लाख) प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त/प्रभावित थे। वर्ष 2004 की सुनामी ने (इसकी) अर्थव्यवस्था को 470 मिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान पहुंचाया जो इसके सकल घरेलू उत्पाद के 64 प्रतिशत के बराबर था और इसकी 14 प्रतिशत जनसंख्या (वर्ष 2009 में) बेघर है।

मालदीव में विकास की उपरोक्त चुनौतियों के अलावा, स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी एक गंभीर चिन्ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, वर्ष 2000 में मालदीव में 226 डॉक्टर (8.4 प्रति 10,000 जनसंख्या) थे। चूंकि उनमें से अधिकांश अप्रवासी थे इसलिए समुदाय स्तर पर संवाद संबंधी कठिनाइयां सामने आईं। हालांकि हाल के वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की उपलब्धता में थोड़ा सुधार हुआ है, फिर भी वर्ष 2010 में विशेषज्ञों की संख्या प्रति दस हजार पर 6 (मालदीव स्वास्थ्य रूपरेखा, स्वास्थ्य एवं लिंग/जेंडर मंत्रालय, मालदीव के अनुसार) के स्तर पर ही है जो इंगित करता है कि इस देश में अभी और अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता भी एक चिन्ता है। उदाहरण के लिए, मध्य तथा दक्षिण मध्य क्षेत्रों में, शिशु मृत्यु दर दक्षिण (क्षेत्र) की तुलना में दोगुनी और उत्तरी एवं उत्तरी मध्य क्षेत्रों की तुलना में भी बहुत अधिक है।

इस देश की अर्थव्यवस्था को 1970 की दशक में पर्यटन प्रारंभ होने से बड़ा सहारा मिला। पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 34 प्रतिशत है जबकि अन्य उद्योग, जैसेकि मछली प्रसंस्करण, नौवहन, नौका निर्माण, नारियल प्रसंस्करण, आभूषण, बुनी चटाई, रस्सी, हस्तशिल्प, प्रवाल और रेत खनन आदि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि मानव विकास रिपोर्ट, 2014 के अनुसार युवा बेरोजगारी दर काफी अधिक 40 प्रतिशत (15-24 आयुवर्ष, 2009-2010) है। इस उच्च बेरोजगारी दर ने समाज के एक वर्ग को उत्तरोत्तर कट्टरवाद की तरफ ढ़केला है। युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार तथा गतिविधियों/विकास के लिए भारत अपने स्तर से प्रयास कर रहा है।

राजनीतिक अस्थिरता और बाधाओं के बावजूद, 2000 के बाद से मालदीव में सभी सरकारों ने देश में समग्र विकास के लिए परिस्थितियों का सृजन करने का प्रयास किया है। विकासात्मक मुद्दों का हल निकालने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नामक विकास का एक नया तरीका अपनाया है। मालदीव के योजना तथा विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को वर्ष 2000 के मध्य में प्रारंभ किया। जनसंख्या विकास समेकन वह मुख्य संकल्पना थी जिसने प्रवाल द्वीप के विकास से ध्यान हटाकर क्षेत्रीय

विकास की ओर लगाया क्योंकि पूर्ववर्ती कार्यक्रम सीमित बजट के कारण कायम न रह सका। यह वर्ष 2007 के सरकार के बजट से प्रदर्शित होता है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र निवेश कार्यक्रम (पीएसआईपी) का 45 प्रतिशत बजट सीधे तौर पर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था। मालदीव सरकार द्वारा की गई एक और उल्लेखनीय पहल विकेन्द्रीकरण अधिनियम था जिसे वर्ष 2010 में पारित किया गया। इस संबंध में सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रावधान विकेन्द्रीकृत किया जाने वाला पहला कार्य है।

भारत द्वारा विकास सहयोग

मालदीव को (दिए जाने वाले) भारत के विकास सहयोग में अनेक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कौशल तथा क्षमता निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। वर्तमान में, द्विपक्षीय सहयोग "व्यवहार मूलक तथा परस्पर लाभकारी पहलों तथा परियोजनाओं" में प्रदर्शित होता है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण विकास सहयोग पहल निम्नलिखित हैं:

- मालदीव में ट्यूना मछली डिब्बाबंदी संयंत्र की स्थापना, जिसकी क्षमता 10,000 डिब्बा प्रतिदिन है।
- वर्ष 2002 में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण स्लॉट 10 से बढ़ाकर 20 करने की घोषणा की।
- प्राकृतिक आपदा से निपटने में मालदीव की सहायता में भारत सरकार की विकास सहायता भी मददगार थी। भारत ने वर्ष 2004 में सुनामी आपदा के पश्चात मालदीव को 10 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता प्रदान की और मई 2007 में ज्वार आने के बाद फिर से 10 करोड़ रूपए की सहायता प्रदान की थी।
- वर्ष 2007-08 में मोहम्मद नशीद की भारत यात्रा के दौरान दोनों सरकारों ने मालदीव को 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त/आपात ऋण सुविधा संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए।
- दोनों देशों ने नवंबर, 2011 में 'विकास हेतु सहयोग पर फ्रेमवर्क करार पर भी हस्ताक्षर किए जिनमें व्यापार तथा निवेश, खाद्य सुरक्षा, मात्स्यकी विकास, पर्यटन, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, संचार एवं संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

- वर्ष 2011 में भारत सरकार ने मालदीव को उनकी अपनी राजकोषीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 10 करोड रूपए की अतिरिक्त/आपात ऋण सुविधा प्रदान की।
- वर्ष 2011 में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र माले में स्थापित किया गया।
- भारत सरकार ने माले में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल स्थापित किया। 69.65 करोड़ रूपए की लागत से संस्थापित इंजीनियरी प्रौद्योगिकी संकाय (पीईटी) और आतिथ्य एवं पर्यटन संकाय (आईएमएफएफएचटीएस) भारत द्वारा सहायता-प्राप्त अन्य संस्थान हैं।
- भारत ने फरवरी, 2012 में अतिरिक्त/आपात ऋण सुविधाओं से 20 मिलियन अमरीकी डॉलर की किश्त जारी की और 50 मिलियन अमरीकी डॉलर एसबीआई ट्रेजरी बॉन्ड्स अगले वर्ष में ले जाने का निर्णय किया।
- मालदीव के राजनयिकों ने विदेशी राजनयिकों के लिए भारतीय विदेश सेवा संस्थान के व्यावसायिक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के तहत भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जनवरी, 2014 में भारत सरकार ने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षाबल (एमएफडीएफ) के लिए समेकित प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण करने का वायदा किया।
- अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के ओवरसीज इन्फ्रास्ट्रक्चर एलाएंस को 485 आवासीय एकक निर्मित करने का ठेका दिया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में विकास सहयोग के बावजूद, वर्ष 2012-13 के दौरान भारत और मालदीव के संबंध मधुर नहीं रहे। इब्राहिम नसीर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए जीएमआर इंडिया के ठेके को रद्द कर देने के मालदीव सरकार के निर्णय और इसके बाद की मालदीव की आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों ने इनके बीच संबंधों में तनाव ला दिया।

हालांकि (इनसे) भारत और मालदीव के बीच विकास सहयोग में कोई बाधा नहीं आई। जनवरी, 2014 में राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामिन की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कार्मिकों के कौशल निर्माण तथा प्रशिक्षण में भारत की सहायता की मांग की। इसलिए, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास भारत द्वारा सहायता का एक और मुख्य घटक रहा जिसके तहत वर्ष 2014 में भारत ने मालदीव के छात्रों को भारतीय शिक्षण संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन प्राप्त करने के लिए 74 छात्रवृत्तियां प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित 5.3 मिलियन डॉलर की प्रौद्योगिकी अंगीकरण परियोजना के

तहत मालदीव के कुल 5530 छात्रों ने वर्ष 2011 में प्रारंभ किए गए पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया है जिसमें 3,053 शिक्षण प्रमाणपत्र, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1674 प्रमाणपत्र तथा आईसीटी संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 803 प्रमाणपत्र शामिल हैं।

उपर्युक्त पहलों के अलावा, भारत और मालदीव को अन्य विविध क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने और मालदीव में नई विकास परियोजनाओं की पहचान करने की जरूरत है। विदेशी मामलों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए मालदीव को सहायता एवं ऋण बजट अनुमान (बीई) 286 करोड़ रूपए था, जो विभिन्न कारणों से वर्ष 2013-14 में घटकर 30 करोड़ रह गया। दोनों देशों को आंतरिक विकास को बढ़ावा देने की अन्य संभावनाओं की तलाश करने और विकास वित्त संस्था की स्थापना के प्रस्ताव और भारत से डीजल, पेट्रोल और विमान इंधन का आयात करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री संपर्क के विकास की संभावनाएं तलाशने की भी जरूरत है।

सहयोग के अवसर तथा चुनौतियां

- जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के साथ-साथ सेवा प्रदायगी की उच्च लागतें एवं संपर्क तथा आधारभूत ढ़ांचे के विकास हेतु धनराशि का अभाव जैसे कुछ कारक प्रवाल द्वीपों में असमान विकास और इस क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाएं प्रारंभ करने में (बाधक) बन रहे हैं।

- जलवायु परिवर्तन पर मालदीव की असुरक्षा तब स्पष्ट हो गई जब वर्ष 2004 में इस द्वीप पर सुनामी आई। ज्यादा बड़े द्वीपों पर लोगों को स्थानान्तरित करने और उन्हें बसाने की मालदीव सरकार की विकास योजना एक जोखिम भरी और जटिल प्रक्रिया है जिसमें आवासों के निर्माण के लिए धनराशि की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इन प्रवाल द्वीपों में आवासीय एककों के निर्माण में बेहतर विशेषज्ञता की जरूरत है ताकि ये ज्वार उठने और पर्यावरण में अचानक आनेवाले परिवर्तनों को सह/झेल सकें।

- चूंकि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए विकेन्द्रीकरण के लिए कार्यरत संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत है जो स्थानीय स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक असमानता और गरीबी के सवाल को प्रभावी ढ़ंग से हल कर सकते हैं।

- आपदा राहत कोष और ऋण सुविधा की व्यवस्था भारत की विकास सहायता के मुख्य घटकों को पर्यटन विकास को ठोस बनाने के कार्यक्रम से जोड़ने की मालदीव सरकार की नीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि समुदायों के स्थानान्तरण से मालदीव की कमजोर लोकतांत्रिक संरचना को क्षति न पहुंचे।

संस्तुतियां

1. प्रवाल द्वीपों में लघु स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वय की संभावनाओं का पता लगाना। इस संबंध में भारत और मालदीव सतत तटीय विकास हेतु मात्स्यकी (ब्लू) उद्योग मॉडल का अध्ययन करने की संभावना तलाश सकते हैं।
2. इस क्षेत्र में लघु उद्योगों और भारतीय निवेश को बढ़ावा देना। इस संबंध में मालदीव की उद्यमशीलता को मजबूत करने के लिए लघु अनुदान परियोजना आधारित पहल का उपयोग किया जा सकता है।
3. प्रवाल द्वीप में कौशल विकास संस्थाओं जैसे अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार।
4. स्वास्थ्य परिचर्या तथा सेवाओं के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना। चूंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में असंतुलन एक चिन्ता है इसलिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और माले से बाहर संस्थाओं के विकास की संभावनाओं का पता लगाना।
5. मालदीव सरकार को एशिया विकास बैंक (एडीबी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संबंधित समुदायों से परामर्श करके उपयुक्त सामाजिक एवं आर्थिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रोत्साहित करना।
6. मौजूदा परियोजनाओं का अनुवीक्षण तथा क्षेत्रीय विकास पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना।

**डॉ. एम. समता विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*